डॉ सुभाष चंद्र पांडे

भारतीय उद्योगों के सामने मुद्दे, चुनौतियाँ और अवसर

भारत में उद्यमों का विशाल आकार और विविधता, व्यवसायों के विनियमन और प्रबंधन के लिए एक समान दृष्टिकोण की अनुमति नहीं देती। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का उद्देश्य नीतियों को एकीकृत, शासन में सुधार तथा भारत को 21वीं सदी के औद्योगिक महाशक्ति में बदलने के लिए एक स्थायी विनिर्माण पारिस्थितिकी-तंत्र को बढ़ावा देना है।

आज़ादी से पहले भारत में छोटे-छोटे हस्तशिल्प और कपड़े बनाने का काम होता था। आज़ादी के बाद सरकार ने बड़े कारखाने और उद्योग शुरू किए। 1991 के बाद आर्थिक सुधार हुए, जिससे निजी कंपनियां और विदेशी निवेश बढ़ा। आज़ाद भारत खेती पर निर्भर देश से बदलकर एक उभरता हुआ औद्योगिक केंद्र बन गया है। उद्योगों का तेज़ी से विस्तार और विविधीकरण हुआ तथा वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा के समक्ष उल्लेखनीय लचीलेपन के साथ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में शामिल हो गए हैं।

1990 के दशक से, भारत का औद्योगिक परिदृश्य एक राज्य-नियंत्रित, संरक्षित अर्थव्यवस्था से एक उदार, वैश्विक रूप से एकीकृत, प्रौद्योगिकी-संचालित प्रणाली में विकसित हुआ है। अब

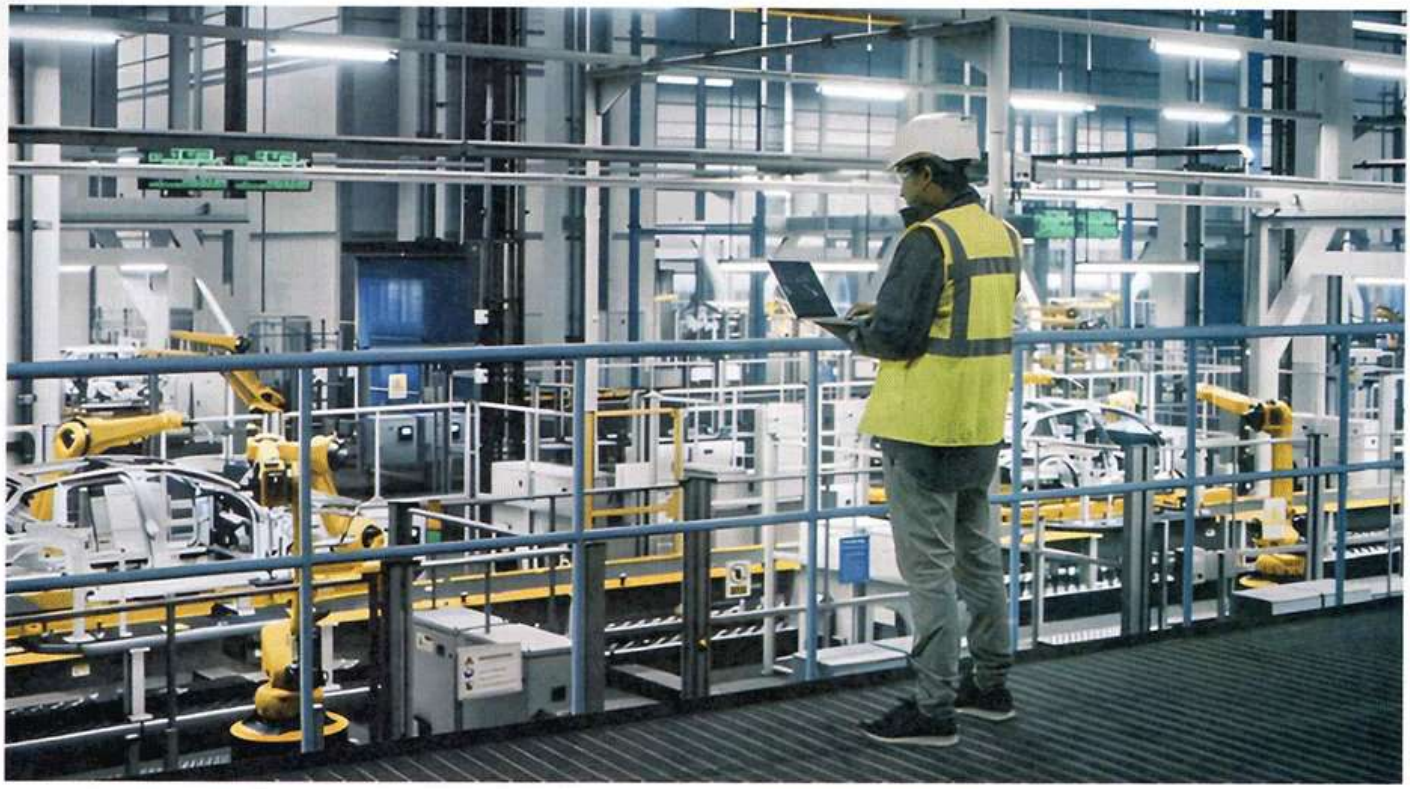

लेखक भारतीय लोक लेखा परीक्षक संस्थान (आईपीएआई) के अध्यक्ष और भारत सरकार के पूर्व विशेष सचिव हैं। ईमेलः scpandey2906@gmail.com

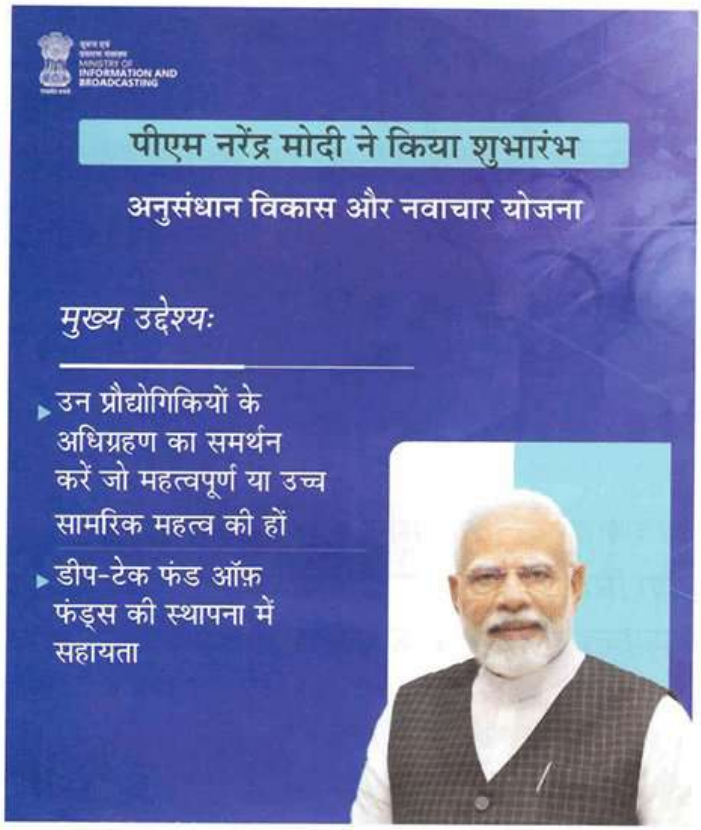

यह नवाचार, स्थिरता और प्रतिस्पर्धात्मकता पर ज़ोर देता है, जिससे भारत एक उभरती हुई औद्योगिक और सेवा शक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है। उच्च तकनीक वाले विनिर्माण की हिस्सेदारी बढ़ाना, रोज़गार की सघनता बढ़ाना, आयात-निर्यात की सघनता कम करना और स्थानीय संसाधनों व कौशल विकास पर आधारित पर्यावरण-अनुकूल, सतत् विकास को आगे बढ़ाना नीति-निर्माताओं और उद्योग जगत के उद्यमियों की प्रमुख प्राथमिकताएँ हैं। प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और युवा कार्यबल सतत् विकास और नवाचार के लिए उपजाऊ ज़मीन प्रदान करते हैं।

औद्योगिक क्षेत्र (खनन/उत्खनन, विनिर्माण, बिजली/गैस/जल उपयोगिताएं और निर्माण) पिछले तीन दशकों से हमारे सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 28-30 प्रतिशत (विनिर्माण लगभग 14-16 प्रतिशत और निर्माण लगभग 8-10 प्रतिशत) का योगदान दे रहा है। आज़ादी के बाद हुए एक बड़े संरचनात्मक परिवर्तन में, प्राथमिक क्षेत्र (कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ) की हिस्सेदारी लगभग 50 प्रतिशत से घटकर लगभग 15 प्रतिशत रह गई है, जबकि तृतीयक/सेवा क्षेत्र में भी इसी अनुपात में वृद्धि हुई है। वैश्विक विनिर्माण उत्पादन में हमारी हिस्सेदारी लगभग 2 प्रतिशत है। भारत वैश्विक विनिर्माण में 2 प्रतिशत से भी कम का योगदान देता है। यह हिस्सेदारी वर्षों से स्थिर रही है।

आज भारतीय उद्योग कपड़ा, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा तक फैले हुए हैं, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। हालांकि, उद्योगों और क्षेत्रों में औद्योगिक विकास असमान है, जबकि प्रणालीगत मुद्दों और चुनौतियों का समाधान किया जा रहा है और प्रौद्योगिकी अपनाने, नीति समर्थन और वैश्विक मांग में बदलाव से टिकाऊ औद्योगिक विकास के लिए नए अवसर दिखाई दे रहे हैं।

1991 की औद्योगिक नीति ने औद्योगिक क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त करके, अधिकांश उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को समाप्त करके, निजीकरण को सक्षम करके और दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मकता और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण बढ़ाने के लिए कई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देकर एक बड़ा बदलाव किया।

सुधारों से प्रतिस्पर्धा, दक्षता और आधुनिकीकरण में वृद्धि हुई। पूंजी-प्रधान और आयात-प्रधान उद्योगों में तीव्र वृद्धि और निर्यात में वृद्धि 1990 के दशक से उल्लेखनीय रुझान रहे हैं।

विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी में दीर्घकालिक स्थिरता (राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 के अनुसार 2025 तक इसे 25 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है); आयात-तीव्रता में लगातार वृद्धि; श्रम-तीव्रता में लगातार गिरावट तथा विनिर्माण उत्पादन में लगभग आधे का योगदान एक ही उद्योग (ऑटोमोबाइल) द्वारा किया जाना, लंबे समय से चिंता का विषय रहे हैं।

आक्रामक ट्रेड यूनियनवाद, वायु/जल प्रदूषण, स्वच्छ जल/बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, उग्रवाद/सुरक्षा मुद्दे और सस्ते आयात विशेष उप-क्षेत्रों (फार्मा, कपड़ा, चमड़ा, धातु और रासायनिक प्रसंस्करण उद्योग) और सीमावर्ती राज्यों जैसे भौगोलिक क्षेत्रों में कम/धीमी/नकारात्मक औद्योगिकीकरण के प्रमुख कारण रहे हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के कई उद्यमों को बदलती आर्थिक और विनियामक स्थितियों के

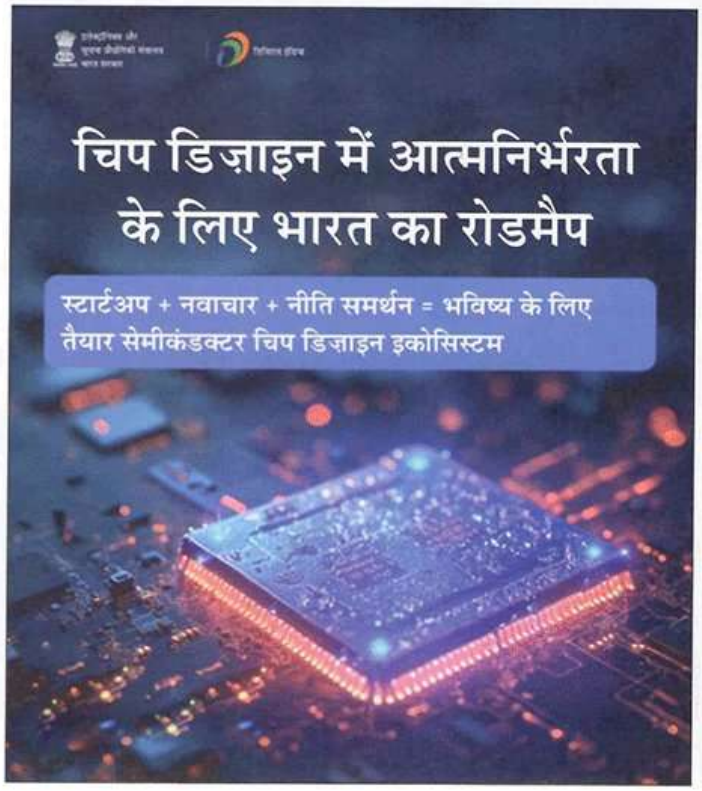

तहत व्यवहार्य बने रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा।

कई फार्मा पीएसयू - इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड और बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड - का चरणबद्ध तरीके से बंद होना, आयातित थोक दवाओं पर बढ़ती निर्भरता के साथ हुआ है। तमिलनाडु में स्टरलाइट कॉपर संयंत्र पर्यावरण संबंधी चिंताओं और सार्वजनिक विरोध के कारण मई 2018 से बंद है, जिससे आयातित तांबे पर निर्भरता बढ़ गई है।

सेवा क्षेत्र रोज़गार सृजन में अग्रणी है, लेकिन 85 प्रतिशत से ज़्यादा 'श्रमिक' असंगठित क्षेत्र के हैं और पूर्ण सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर हैं। उनकी सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करने और उन्हें सामान्य कल्याणकारी योजनाओं में शामिल करने के प्रयास जारी हैं।

औद्योगिक क्षेत्र अत्यधिक विखंडित है, जिसमें लगभग 7 करोड़ एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) हैं, जो सभी व्यावसायिक उद्यमों का लगभग 99 प्रतिशत हिस्सा हैं। इससे उद्यमशीलता और लचीलेपन को बढ़ावा मिलता है, लेकिन साथ ही पैमाने की अर्थव्यवस्था कम होती है, उत्पादन लागत बढ़ती है, गुणवत्ता संबंधी समस्याएँ पैदा होती हैं और वैश्विक बाज़ारों में सौदेबाज़ी कमज़ोर होती है। यहाँ एक वास्तविक नीतिगत दुविधा है। वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी उत्पाद बनाने के लिए, हमें बड़े पैमाने पर उत्पादन और मानकों व विशिष्टताओं की विविधता में कमी की आवश्यकता है, लेकिन इससे अनिवार्य रूप से रोज़गार की तीव्रता में कमी, एकाधिकार का उदय और उससे जुड़े जोखिम पैदा होंगे।

भारत में उद्यमों का विशाल आकार और विविधता, व्यवसायों के नियमन और प्रबंधन के लिए एक समान दृष्टिकोण की अनुमति नहीं देती। धन शोधन, कर चोरी या अन्य संदिग्ध उद्देश्यों से बनाई गई फर्जी कंपनियों को हटाने के हालिया अभियानों के बाद भी, लगभग 29 लाख पंजीकृत कंपनियों में से एक-तिहाई अभी भी निष्क्रिय हैं। इससे नियामक प्रणाली पर दबाव का अंदाजा लगाया जा सकता है।

उच्च लॉजिस्टिक्स लागत सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 14 प्रतिशत है, जबकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में यह 8-10 प्रतिशत है। बिजली की कमी और अविश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति, विशेष रूप से ऊर्जा-गहन उद्योगों के लिए, विनिर्माण दक्षता में बाधा डालती है। खराब परिवहन संपर्क लॉजिस्टिक्स लागत को बढ़ाता है और प्रतिस्पर्धात्मकता को कम करता है। हाल के वर्षों में औद्योगिक केन्द्रों, परिवहन गलियारों और बंदरगाहों तथा बाज़ारों के बीच रेल/सड़क/हवाई सम्पर्क में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण निवेश किया गया है ताकि सड़कों, रेलवे, हवाई और समुद्री बंदरगाहों तथा विद्युत आपूर्ति के विनिर्माण विस्तार की गति में तेज़ी लाई जा सके। चल रहे राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा जैसे औद्योगिक गलियारों का विकास, 550 जिला मुख्यालयों को न्यूनतम 4-लेन राजमार्ग से जोड़ने का लक्ष्य रखने वाली भारतमाला परियोजना, सागरमाला (समुद्री और बंदरगाह अवसंरचना विकास के लिए), समर्पित माल ढुलाई गलियारे, रेलवे का पूर्ण विद्युतीकरण और 10000 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) बंदरगाह क्षमता का लक्षित विस्तार, ये सभी अवसंरचना विकास के लिए एक बड़े प्रयास का हिस्सा हैं।

उद्योग जगत को क्रॉस-सब्सिडी का भारी बोझ झेलना पड़ रहा है। रेलवे अपने यात्री क्षेत्र में घाटे की भरपाई के लिए माल ढुलाई पर बढ़े हुए टैरिफ का इस्तेमाल करता है। कृषि और घरेलू क्षेत्रों पर टैरिफ कम करने के लिए औद्योगिक बिजली को ऊंचे टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। इन क्रॉस-सब्सिडियों से उद्योगों की लागत बढ़ जाती है और इससे रेल माल ढुलाई का बड़ा हिस्सा सड़क माल ढुलाई और निजी बिजली उत्पादन की ओर चला जाता है, का दूरगामी आर्थिक असर हो।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

आत्मनिर्भर भारत की एक खुराक

'मेक इन इंडिया' भारत की वैश्विक औषधि पहचान में बदलाव ला रहा है

भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग का अवलोकन

- मात्रा के हिसाब से दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा और मूल्य के मामले में 11वें स्थान पर
- वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल वार्षिक कारोबार 4,17,345 करोड़ रहा
- पिछले 5 वर्षों में औसत वृद्धि दर 10.08 प्रतिशत रही

चौथी औद्योगिक क्रांति (उद्योग 4.0) भारतीय उद्योगों के लिए अवसर और चुनौतियाँ दोनों प्रस्तुत कर रही है। पारंपरिक स्वचालन से आगे बढ़कर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (आईओटी) और उन्नत विश्लेषण, उत्पादकता बढ़ाने, लागत कम करने और नवाचार-संचालित विकास को सक्षम बनाने के लिए उत्पादन प्रक्रियाओं में बदलाव ला रहे हैं। हमें इन तकनीकों को अपनाना होगा, अन्यथा इनके अप्रचलित होने का जोखिम है। इन्हें अपनाना महंगा है और इसके लिए कुशल श्रम और अनुसंधान एवं विकास में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है। फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और एयरोस्पेस जैसे उद्योगों में तकनीक-आधारित विस्तार की अपार संभावनाएँ हैं।

ग्राहक न केवल उत्पाद खरीदने के लिए उत्सुक हैं, बल्कि अपनी कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संपूर्ण सिस्टम समाधान भी चाहते हैं। साझा अर्थव्यवस्था (खरीदने/स्वामित्व के बजाय पट्टे/किराए पर लेने) के उद्भव और उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव का उद्योगों के व्यावसायिक मॉडलों पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीकें (3डी प्रिंटिंग) उपभोक्ता उत्पादों को बड़े पैमाने पर अनुकूलित करने की अनुमति देती हैं, जो समझदार ग्राहकों की अत्यधिक व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। यह विकेन्द्रीकृत, छोटे पैमाने पर उत्पादन को संभव बनाती है, जिससे पारंपरिक, प्रदूषणकारी कारखानों की एक ही छत के नीचे बड़े पैमाने पर उत्पादन की आवश्यकता कम हो जाती है।

जनसांख्यिकीय लाभांश भारतीय उद्योगों के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करता है। हमारे पास दुनिया की सबसे युवा आबादी है, जो एक विशाल, लागत-प्रतिस्पर्धी श्रम-शक्ति के साथ-साथ एक विशाल उपभोक्ता आधार प्रदान करती है, जो सही कौशल और नीतिगत समर्थन के साथ दशकों तक औद्योगिक विकास को बनाए रखने में सक्षम है।

घरेलू उपभोक्ताओं के लिए स्थानीय संसाधनों पर आधारित बड़े पैमाने पर उत्पादन और हरित/टिकाऊ उत्पादों की ओर बढ़ता रुझान, इलेक्ट्रिक वाहनों, ऊर्जा भंडारण, नवीकरणीय ऊर्जा (सौर/पवन) और पर्यावरण अनुकूल विनिर्माण प्रथाओं में नए अवसर प्रस्तुत करता है। भारतीय उद्योग पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करते हुए प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए इन क्षेत्रों में नवाचार का लाभ उठा सकते हैं।

2020 में शुरू की गई उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना में 14 क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जो 1.76 लाख करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करते हैं, 2025 के मध्य तक कुल बिक्री 16.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक होगी, जिससे 12 लाख से अधिक प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोज़गार सृजित होंगे।

इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उद्योगों में मूल्य-संवर्धन श्रृंखला को आगे बढ़ाने की अपार संभावनाएँ हैं। पीएलआई, इस उप-क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 76,000 करोड़ रुपये के पैकेज द्वारा समर्थित सेमीकंडक्टर मिशन के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। हाल के वर्षों में रक्षा विनिर्माण और निर्यात में लगातार वृद्धि से हमारे विनिर्माण विकास को बढ़ावा मिला है।

रक्षा जैसे पूंजी-प्रधान उद्योगों के लिए, प्रतिस्पर्धी लागत पर बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए घरेलू मांग अपर्याप्त है। निर्यात मांग भी आवश्यक है। कड़ी प्रतिस्पर्धा, वैश्विक अनिश्चितताओं और नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्थाओं के पतन के बीच यह एक चुनौती है।

अंतरराष्ट्रीय संबंधों में स्थायी और शत-प्रतिशत मित्र या शत्रु दुर्लभ होते हैं क्योंकि देश अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाते हैं। हमें निकट भविष्य में होने वाले आश्चर्यों से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है और कुशल कार्यबल और मज़बूत बुनियादी ढाँचे का निर्माण जारी रखना चाहिए। विशाल घरेलू मांग पैदा करने और उसे पूरा करने के लिए नीतिगत समर्थन और उद्योग जगत की कार्रवाइयों का समन्वय ज़रूरी है। हमें भारत को गुणवत्ता के पर्याय के रूप में स्थापित करना होगा और देश को शर्मसार करने वाली बेकार व्यावसायिक इकाइयों को नष्ट होने देना होगा (घातक कफ सिरप की घटनाओं का संदर्भ)।

हम एक सेवा-प्रधान/उपभोग-प्रधान अर्थव्यवस्था हैं जो पिछले 10 वर्षों में वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में मज़बूत एकीकरण के साथ दसवें स्थान से चौथे स्थान पर पहुँच गई है। भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढाँचे में भारी निवेश और कर सुधारों ने एक अनुकूल व्यावसायिक वातावरण को बढ़ावा दिया है। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का उद्देश्य नीतियों को एकीकृत, शासन में सुधार करना तथा भारत को 21वीं सदी के औद्योगिक महाशक्ति में बदलने के लिए एक स्थायी विनिर्माण पारिस्थितिकी-तंत्र को बढ़ावा देना है। ❑